



**VAJIRAO & REDDY INSTITUTE**

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918171181080  
+919068806410



www.vajiraoinstitute.com  
info@vajiraoinstitute.com



# TODAY ANALYSIS

(आज का विश्लेषण)

(06 September 2023)

## Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

## Important News:

- "इंडिया, यानी भारत": ऋग्वेद से लेकर भारत के संविधान तक, राष्ट्र के नाम का संक्षिप्त इतिहास
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो परिसंपत्ति सहित 'फिनटेक (Fintech)' के महत्व एवं चुनौतियों पर प्रकाश डाला
- जल जीवन मिशन ने 13 करोड़ ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन लगाने की उपलब्धि हासिल की
- पारिस्थितिकी हत्या (Ecocide) को अपराध घोषित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

## ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



**VAJIRAO & REDDY INSTITUTE**

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918171181080  
+919068806410



www.vajiraoinstitute.com  
info@vajiraoinstitute.com



## "इंडिया, यानी भारत": ऋग्वेद से लेकर भारत के संविधान तक, राष्ट्र के नाम का संक्षिप्त इतिहास

### मुद्दा क्या है?

- भारत के विपक्षी राजनीतिक दल G20 रात्रिभोज के आधिकारिक निमंत्रण की तस्वीरें साझा कर रहे हैं जहां मेजबान को सामान्य "प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया" के बजाय "प्रेसिडेंट ऑफ़ भारत" लिखा गया है।
- इससे आधिकारिक तौर पर देश का नाम 'इंडिया' से 'भारत' में बदलने की संभावना के बारे में चर्चा शुरू हो गई है।



ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



## संवैधानिक प्रावधान:

- उल्लेखनीय है कि ही देश का संविधान पहले से ही अनुच्छेद 1 में दोनों नामों का परस्पर उपयोग करता है: "इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा"।
- जून 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान से "इंडिया" को हटाने और "इस देश के नागरिकों को औपनिवेशिक अतीत से छुटकारा पाने को सुनिश्चित करने" के लिए केवल भारत को बनाए रखने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि "'इंडिया' को संविधान में पहले से ही 'भारत' कहा गया है"।

## 'भारत' नाम कहां से आया?

- 'भारत' नाम की उत्पत्ति पुराणों और महाकाव्य महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों से हुई है। इन ग्रंथों के अनुसार भारत का वर्णन दक्षिणी समुद्र और बर्फीले उत्तरी क्षेत्र के बीच स्थित क्षेत्र के रूप में किया गया है। सामाजिक वैज्ञानिक कैथरीन क्लेमेंटिन-ओझा भारत की व्याख्या एक ऐसे शब्द के रूप में करती हैं जो राजनीतिक या भौगोलिक के बजाय एक धार्मिक और सामाजिक-सांस्कृतिक इकाई का प्रतिनिधित्व करता है।
- 'भरत' नाम एक प्राचीन पौराणिक राजा से भी जुड़ा है, जिन्हें ऋग्वैदिक लोगों का पूर्वज माना जाता है जिन्हें भरत के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोगों के पूर्वज होने के नाते जुड़ा हुआ है।

### ADDRESS:



- जनवरी 1927 में लिखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने "भारत की मौलिक एकता (Fundamental unity of India)" का उल्लेख किया जो प्राचीन काल से अस्तित्व में है। उन्होंने इस एकता को साझा आस्था और संस्कृति के रूप में उजागर किया, जहां इंडिया को अक्सर पवित्र भूमि 'भारत' के रूप में जाना जाता था।

### प्राचीन नामों को अपनाने की मांग क्यों हो रही है?

- देशों, स्थानों, संस्थाओं और सांस्कृतिक तत्वों के लिए प्राचीन या पारंपरिक नामों के उपयोग की मांग अक्सर कई कारणों से उठती रही है:
- लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और सम्मान देने के लिए प्राचीन नामों के उपयोग की वकालत कर सकते हैं।
- कुछ मामलों में, प्राचीन नामों का उपयोग राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय पहचान के दावे से जुड़ा हुआ है। कई देश औपनिवेशिक शासन के अधीन थे, जिसके दौरान औपनिवेशिक शक्तियां अक्सर स्थानों और संस्थाओं पर अपना नाम थोपती थीं। प्राचीन नामों की मांग इस औपनिवेशिक विरासत की अस्वीकृति और सांस्कृतिक पहचान की पुनः प्राप्ति हो सकती है।
- कुल मिलाकर सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और इतिहास और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने की इच्छा को दर्शाता है।

**साभार: The Indian Express**

#### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



**VAJIRAO & REDDY INSTITUTE**

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918171181080  
+919068806410



www.vajiraoinstitute.com  
info@vajiraoinstitute.com



## वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो परिसंपत्ति सहित 'फिनटेक (Fintech)' के महत्व एवं चुनौतियों पर प्रकाश डाला:

- भारत की वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, निर्मला सीतारमण ने वित्तीय प्रणाली के लिए वैश्विक खतरों पर प्रकाश डाला है, जिसमें क्रिप्टोकॉर्सेसी, साइबर घुसपैठ, ड्रग माफिया, टैक्स हेवेन और कर चोरी शामिल हैं।
- उन्होंने मुंबई में चल रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2023 में प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया और फिनटेक उद्योग से उपयोगकर्ता डेटा और वित्तीय लेनदेन की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों में निवेश करने का आग्रह किया।



**ADDRESS:**

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



## वित्त मंत्री द्वारा कही गई प्रमुख बातें:

- वित्त मंत्री के अनुसार भारत वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को समावेशी, लचीला और टिकाऊ बनाने में नेतृत्व कर सकता है। हमारे पास उपकरण हैं लेकिन हमें इसे जिम्मेदार बनाना होगा। इसलिए हमें वैश्विक सहयोग की जरूरत है।
- वित्त मंत्री ने G20 की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में 'सीमा पार भुगतान' में सुधार और जानकारी साझा करने के भारत के लक्ष्य पर भी चर्चा की। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक वार्षिक सीमा-पार भुगतान वर्तमान में 20 ट्रिलियन डॉलर है और लेनदेन लागत लगभग 120 बिलियन डॉलर है। 2022 तक, भारत प्रेषण का अग्रणी प्राप्तकर्ता है, लगभग 100 बिलियन डॉलर प्राप्त कर रहा है।
- प्रेषण (रेमिटेन्स) की यह पर्याप्त मात्रा सीमा पार भुगतान प्रणालियों को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता के लिए एक मजबूत प्रेरक के रूप में कार्य करती है। इन प्रणालियों में सुधार करना भारत का मुख्य फोकस रहा है और G20 समूह के भीतर इस पर चर्चा की गई है।
- उन्होंने उल्लेख किया कि IMF और FSB जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने क्रिप्टोकॉर्सेसी पर पेपर जारी किए हैं। उन्होंने वित्तीय प्रणाली को अधिक समावेशी बनाने में फिनटेक की भूमिका पर जोर दिया और भारत के वित्तीय परिदृश्य पर इसके बढ़ते प्रभाव का उल्लेख किया।
- वित्त मंत्री के अनुसार वर्तमान में, फिनटेक एक मजबूत और गतिशील वित्तीय समावेशन उपकरण बन गया है। 2022 BCG मैट्रिक्स रिपोर्ट के अनुसार, ऋण देने

ADDRESS:



में, जो बैंकों के मुख्य व्यवसायों में से एक है, फिनटेक के पास नए-क्रेडिट ग्राहकों की 36% हिस्सेदारी थी, जबकि ईंट-और-मोर्टार (सामान्य) बैंकों की 22% हिस्सेदारी थी। फिनटेक ऋण देने में भी कहीं अधिक पहुंच रखते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो एक पारंपरिक बैंक नहीं कर रहा है।

- ऐसे में, वित्त मंत्री ने वित्तीय समावेशन और सुरक्षा को बढ़ावा देने में फिनटेक उद्योग की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए सहयोग के माध्यम से वैश्विक वित्तीय खतरों को संबोधित करने के महत्त्व पर जोर दिया।

## फिनटेक क्या है?

- फिनटेक, जिसका संक्षिप्त रूप "वित्तीय प्रौद्योगिकी" है, वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और वित्तीय प्रणालियों की दक्षता में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार के उपयोग को संदर्भित करता है।
- फिनटेक कंपनियां और स्टार्टअप मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन भुगतान, पीयर-टू-पीयर लेंडिंग, डिजिटल वॉलेट, रोबो-सलाहकार और बहुत कुछ सहित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करने के लिए सॉफ्टवेयर, ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हैं।
- फिनटेक का लक्ष्य व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ, सुविधाजनक और लागत प्रभावी बनाना है, साथ ही वित्तीय उद्योग में नवाचार को बढ़ावा देना है।

### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



**VAJIRAO & REDDY INSTITUTE**

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918171181080  
+919068806410

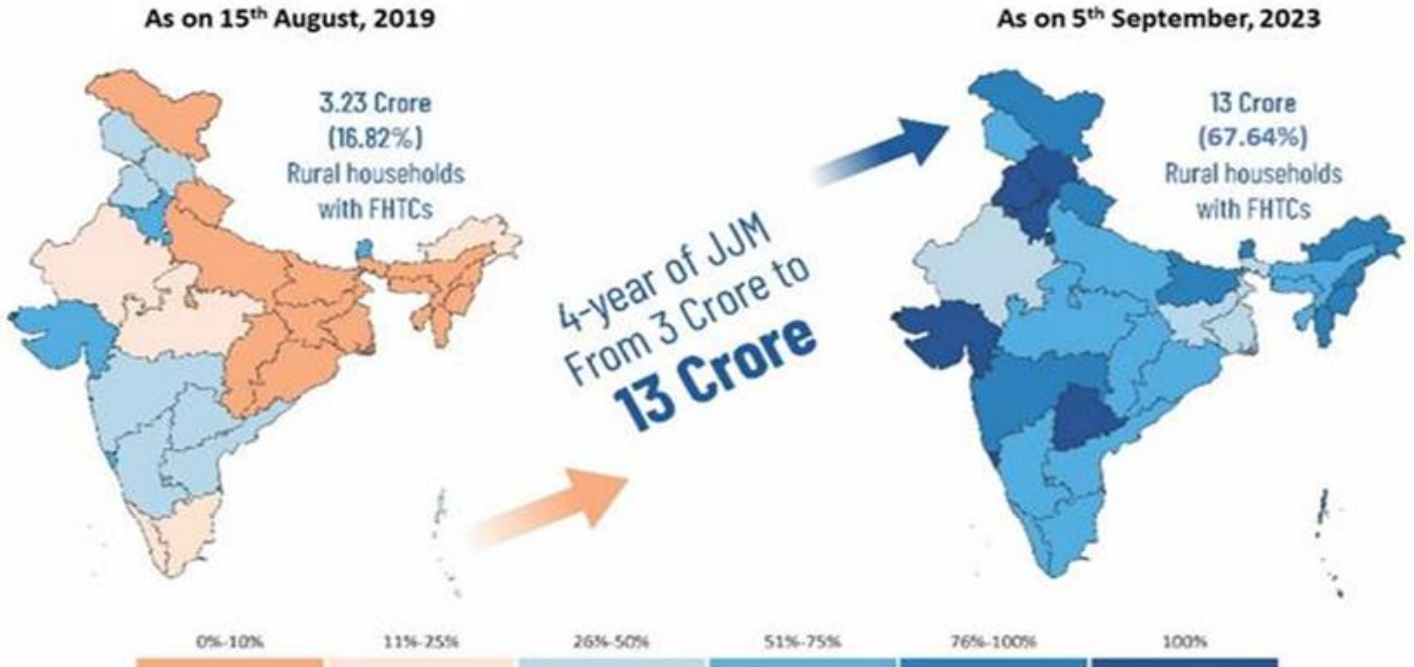


www.vajiraoinstitute.com  
info@vajiraoinstitute.com



## ‘जल जीवन मिशन’ ने 13 करोड़ ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन लगाने की उपलब्धि हासिल की:

- जल जीवन मिशन (जेजेएम) ने आज 13 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करके एक और उपलब्धि हासिल की है।
- जीवन बदल देने वाले मिशन की शुरुआत ‘वृहद गति और पैमाने’ के साथ काम करने के लिए हुई है।



**ADDRESS:**

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)





## ‘जल जीवन मिशन’:

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2019 को ‘जल जीवन मिशन’ की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराना है।
- 2019 में मिशन की शुरुआत होने के समय, 19.35 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से सिर्फ 3.23 करोड़ (16.72 फीसदी) परिवारों के पास नल का पानी उपलब्ध था। पिछले 4 वर्षों में यह आंकड़ा बढ़कर 13 करोड़ पर पहुंच चुका है।

## प्रमुख आंकड़े:

- अब तक, 6 राज्यों अर्थात् गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश) और 3 केंद्र शासित प्रदेशों - पुदुचेरी, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने 100 प्रतिशत कवरेज की सूचना दी है। निकट भविष्य में बिहार 96.39 प्रतिशत पर, मिजोरम 92.12 प्रतिशत पर परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए तैयार हैं।
- गोवा, हरियाणा, पंजाब, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, दादरा व नगर हवेली और दमन और दीव 'हर घर जल प्रमाणित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी, इन

### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



**VAJIRAO & REDDY INSTITUTE**

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918171181080  
+919068806410



www.vajiraoinstitute.com  
info@vajiraoinstitute.com



राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, ग्रामीणों ने ग्राम सभाओं के माध्यम से पुष्टि की है कि गांव में 'सभी घर और सार्वजनिक संस्थानों' को पानी की पर्याप्त, सुरक्षित और नियमित आपूर्ति हो रही है।

- देश के 145 जिलों और 1,86,818 गांवों ने 100 प्रतिशत कवरेज की सूचना दी है।
- मिशन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में कार्यक्रम को कार्यान्वित करता है और यह विकास भागीदारों सहित सभी के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है कि रूपांतरकारी बदलाव जमीन पर देखा जाता है।

3 Crore to  
**13** CRORE  
Rural Households  
with tap water  
in just 4 years

Har Ghar Jal  
Jal Jeevan Mission  
Bringing Smiles

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



## ‘जल जीवन मिशन’ से लाभ:

- 'हर घर जल' के तहत काम के परिणामस्वरूप ग्रामीण आबादी को महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक लाभ हो रहा है। नियमित नल जल आपूर्ति से लोगों, विशेषकर महिलाओं और युवा लड़कियों को अपनी दैनिक घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी से भरी बाल्टी ढोने की सदियों पुरानी मेहनत से राहत मिली है। बचे हुए समय का उपयोग आय सृजन गतिविधियों, नए कौशल सीखने और बच्चों की शिक्षा में सहायता के लिए किया जा सकता है।
- योजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए, शुरू से ही सामुदायिक भागीदारी ग्रामीण पाइप लाइन जलापूर्ति योजनाओं की योजना, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के केंद्र में रही है।
- जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय, 1.79 करोड़ आबादी (आर्सेनिक-1.19 करोड़, फ्लोराइड-0.59 करोड़) वाली 22,016 बस्तियां पेयजल स्रोतों में आर्सेनिक/फ्लोराइड संदूषण से प्रभावित थीं। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की रिपोर्ट के अनुसार, अब सभी आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है।

### ADDRESS:



## पारिस्थितिकी हत्या (Ecocide) को अपराध घोषित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासः

### चर्चा में क्यों है?

- मेक्सिको में 'माया ट्रेन परियोजना' पर मिश्रित राय है। कुछ लोग इसे प्राचीन मिस्र में पिरामिडों के निर्माण की तरह एक बहुत बड़ी और महंगी परियोजना कहते हैं। यह 1,525 किलोमीटर का लंबा रेल मार्ग है जो कैरेबियन में पर्यटकों को महत्वपूर्ण माया ऐतिहासिक स्थानों से जोड़ता है और इसकी लागत 20 अरब डॉलर है।
- दूसरी ओर, कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक बहुत ही हानिकारक परियोजना है जो बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकती है। इसे "Megaproject of Death" भी कहा जा रहा है। यह युकाटन प्रायद्वीप की प्राकृतिक सुंदरता को नुकसान पहुंचा सकता है, प्राचीन गुफाओं को नुकसान पहुंचा सकता है और वहां रहने वाले स्वदेशी लोगों के समुदायों को नुकसान पहुंचा सकता है।
- वास्तव में, प्रकृति के अधिकारों से संबंधित एक विशेष अदालत ने अगस्त में कहा था कि यह परियोजना पर्यावरण और इन स्वदेशी समुदायों की संस्कृति को गंभीर

#### ADDRESS:



नुकसान पहुंचा रही है। अदालत ने कहा कि यह परियोजना "पारिस्थितिकी हत्या (Ecocide) और नृजातीय हत्या (Ethnocide) के अपराध" का कारण बनती है।



## ‘पारिस्थितिकी हत्या (Ecocide)’ क्या है?

- पारिस्थितिकी हत्या (Ecocide), ग्रीक और लैटिन से लिया गया है, जिसका अनुवाद 'स्वं के घर' या 'पर्यावरण' को मारना है। इकोसाइड का अर्थ है हमारे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाना, जैसे प्रकृति को नष्ट करना या नदियों को प्रदूषित करना। इसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली बड़ी निर्माण परियोजनाएं जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं।

### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- आर्थर गैलस्टन नामक एक जीवविज्ञानी ने पर्यावरणीय क्षति को नरसंहार से जोड़ा था, जो लोगों के खिलाफ एक गंभीर अपराध है। लेकिन हमारे मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कानून पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने को अपने आप में कोई बड़ा अपराध नहीं मानते हैं।
- कुछ लोग का मानना है कि हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने को लोगों को नुकसान पहुंचाने जितना ही गंभीर बनाने के लिए कानूनों में बदलाव करना चाहिए। वे इकोसाइड नामक एक नया कानून जोड़ना चाहते हैं।
- 2021 में वकीलों के एक समूह ने पर्यावरण-हत्या को पर्यावरण के लिए हानिकारक चीजें करने के रूप में परिभाषित करने का प्रस्ताव रखा, यह जानते हुए कि इससे गंभीर और स्थायी क्षति होगी। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने को मानवता के विरुद्ध अपराध की ही श्रेणी में रख देगा।
- उन्होंने प्रस्तावित किया कि इकोसाइड, "गैरकानूनी या अनियंत्रित कृत्य है जो इस ज्ञान के साथ किया जाता है कि उन कृत्यों के कारण पर्यावरण को गंभीर और व्यापक या दीर्घकालिक क्षति होने की पर्याप्त संभावना है"।

**ADDRESS:**

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



## ‘पारिस्थितिकी हत्या (Ecocide)’ अपराध क्यों होना चाहिए?

- 11 देशों में इकोसाइड को अपराध माना जाता है, और 27 अन्य देश पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए कानून बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जब यह जानबूझकर किया जाता है और लोगों, जानवरों और पौधों को नुकसान पहुंचाता है। हाल ही में, यूरोपीय संसद ने सर्वसम्मति से पर्यावरण-हत्या को कानूनी अपराध बनाने के लिए मतदान किया।
- इकोसाइड या पारिस्थितिकी-संहार कानूनों वाले अधिकांश देशों में, पौधों और जानवरों को बड़ी क्षति पहुंचाने, हवा या पानी को प्रदूषित करने, या ऐसे कार्य करने जैसी चीजों को दंडित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो एक बड़ी पर्यावरणीय आपदा का कारण बन सकते हैं।
- पर्यावरण कानूनों की विशेषज्ञ नबीला सिद्दीकी का कहना है कि पारिस्थितिकी-संहार कानूनों का उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है कि पर्यावरण को "महत्वपूर्ण नुकसान" का क्या मतलब है और इस नुकसान के परिणाम क्या होने चाहिए। ये कानून लोगों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराएंगे।
- उदाहरण के लिए, यदि पारिस्थितिकी-संहार कानून पहले मौजूद होते, तो वे अमेज़न में वनों की कटाई, हानिकारक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की प्रथाओं, या यहां तक कि 1984 में भयानक भोपाल गैस त्रासदी जैसे मुद्दों को रोकने में मदद कर सकते थे।

### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



## भारत का रुख क्या रहा है?

- भारत में, अदालती फैसलों में 'इकोसाइड' शब्द का कुछ उल्लेख किया गया है, लेकिन यह अभी तक कानून में पूरी तरह से स्थापित अवधारणा नहीं बन पाया है।
- भारत में वायु और जल प्रदूषण को रोकने के नियमों के साथ-साथ विभिन्न पर्यावरण कानून हैं जैसे 1986 का पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, और प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (CAMPA)।
- कानूनी प्रणाली में पारिस्थितिकी-हत्या और प्रकृति के अधिकारों जैसे मुद्दों को ठीक से संबोधित करने के लिए, विशेषज्ञों का सुझाव है कि इन अलग-अलग कानूनों को एक कोड में जोड़ा जाना चाहिए, और संस्थानों को अधिक कुशलता से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इससे पारिस्थितिकी-हत्या और प्रकृति के अधिकारों के बारे में चर्चा करने में मदद मिलेगी और सही कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा सकेगा।

### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)